THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.27

आधुनिक भारत एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था : स्वरूप, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

डॉ. संतोष कुमार भारती
सहायक प्राध्यापक, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर, उत्तर-प्रदेश, भारत
Email- sankumar4464@gmail.com

सार (Abstract):

शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, डिजिटल परिवर्तन तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्संरचना के इस युग में भारत तीव्र गति से आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। शोध पत्र का उद्देश्य आधुनिक भारत की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप का समालोचनात्मक अध्ययन करना है।

यह शोध राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव, डिजिटल शिक्षा की भूमिका, समावेशन, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना का विश्लेषण करता है। साथ ही इसमें असमानता, रोजगार की कमी, आधारभूत संरचना की सीमाएँ तथा डिजिटल विभाजन जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है।

अंततः यह शोध पत्र शिक्षा व्यवस्था को अधिक शिक्षार्थी-केंद्रित, रोजगारोन्मुख, मूल्यपरक एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु रणनीतिक सुधारों का सुझाव प्रस्तुत करता है। आधुनिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि नवाचार, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास को विकसित करना भी होना चाहिए।

मुख्य शब्दः *आधुनिक भारत, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, शैक्षिक सुधार*

1. प्रस्तावना (Introduction):

भारत अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आज विश्व के तीव्र गति से विकसित होने वाले देशों में से एक है। आधुनिक भारत की अवधारणा लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय तथा तकनीकी प्रगति पर आधारित है। इस परिवर्तन प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्रीय एकता का प्रभावी माध्यम है।

21वीं सदी में वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। पारंपरिक शिक्षण पद्धति अब तकनीक-आधारित, संवादात्मक और शिक्षार्थी-केंद्रित बन रही है।

आधुनिक भारत एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है जहाँ परंपरा और आधुनिकता, स्थानीयता और वैश्विकता, तथा ज्ञान और कौशल के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती निरंतर बनी हुई है। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। वर्तमान समय में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता का प्रमुख आधार बन चुकी है।

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बहुआयामी और व्यापक है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तर सम्मिलित हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और डिजिटलीकरण के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट कक्षाएँ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई तकनीकों ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और रोचक बना दिया है। National Education Policy 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक और कौशलआधारित बनाने का प्रयास किया गया है-, जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके।

हालाँकि, इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, डिजिटल विभाजन, संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा की कमी जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षाकेन्द्रित प्रणाली-, रटने की प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यों के ह्रास जैसी चिंताएँ भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

इन चुनौतियों के साथआधारित शिक्षा-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएँ भी निहित हैं। कौशल-, डिजिटल तकनीक का समुचित उपयोग, समावेशी शिक्षा का विस्तार, तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि इन संभावनाओं का समुचित उपयोग किया जाए, तो शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम बनेगी, बल्कि यह भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और ज्ञान आधारित समाज के रूप में-स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

अतः स्पष्ट है कि आधुनिक भारत की प्रगति और सशक्तिकरण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की भूमिका केंद्रीय और निर्णायक है। एक संतुलित, समावेशी और नवाचारप्रधान शिक्षा प्रणाली ही देश को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकती है।-

2. आधुनिक भारत की अवधारणा एवं दृष्टि:

आधुनिक भारत परंपरा और प्रगति का समन्वय है। यह लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

आधुनिक भारत की दृष्टि समावेशी विकास, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहभागिता पर आधारित है। इसके लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो बौद्धिक रूप से सक्षम, नैतिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से उत्तरदायी हों।

3. भारत में शिक्षा का ऐतिहासिक विकास:

प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें समग्र विकास और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। मध्यकाल में मदरसों और पाठशालाओं का विकास हुआ।

ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सार्वभौमिकरण, विश्वविद्यालयों, IITs, IIMs और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया।

4. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप:

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. विद्यालयी शिक्षा
2. उच्च शिक्षा
3. तकनीकी शिक्षा
4. व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा

आज शिक्षा में बहुविषयकता, लचीलापन और दक्षता-आधारित मूल्यांकन पर बल दिया जा रहा है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। इसके प्रमुख बिंदु हैं:

- सार्वभौमिक शिक्षा
- गुणवत्ता सुधार
- बहुविषयक शिक्षा
- तकनीकी एकीकरण
- अनुसंधान को बढ़ावा

6. आधुनिक भारत में शिक्षा का महत्व :

आधुनिक भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख इंजन माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बनती है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति अपने सामाजिक- आर्थिक स्तर कोसुधार सकता है। इसके माध्यम से समान अवसरों की स्थापना होती है, जो सामाजिक न्याय और समावेशिता को सुदृढ़ करती है।

आर्थिक दृष्टि से शिक्षा मानव संसाधन को कुशल और उत्पादक बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। एक शिक्षित कार्यबल नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों—जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व—को विकसित करती है, जिससे नागरिकों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है।

सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा भारतीय परंपराओं, भाषाओं और मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है।

7. शिक्षा का डिजिटलीकरण :

डिजिटलीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। Digital India, SWAYAM और DIKSHA जैसी पहलें शिक्षा को सुलभ, लचीला और व्यापक बनाने में सहायक रही हैं।

ऑनलाइन कक्षाओं, ईलर्निंग प्लेटफॉर्म-, डिजिटल कंटेंट और वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से शिक्षा अब समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो गई है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में- रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है।

हालाँकि, डिजिटल विभाजन (Digital Divide) एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इंटरनेट, उपकरणों और तकनीकी ज्ञान की असमानता शिक्षा की समानता को प्रभावित करती है। अतः आवश्यक है कि डिजिटल संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए।

8. राष्ट्र निर्माण में उच्च शिक्षा की भूमिका :

उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्र के बौद्धिक और नवाचारात्मक विकास के केंद्र होते हैं। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान न केवल ज्ञान का सृजन करते हैं, बल्कि नए विचारों, तकनीकों और समाधानों को विकसित कर समाज की समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

उच्च शिक्षा छात्रों में नेतृत्व क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन और शोध प्रवृत्ति को विकसित करती है। यह उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान सुदृढ़ कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, उच्च शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

9. कौशल विकास और रोजगार :

भारतीय शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से शिक्षा और रोजगार के बीच एक अंतर (Skill Gap) देखा जाता रहा है। अधिकांश विद्यार्थी सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक कौशल की कमी के कारण वे रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते।

कौशल आधारित शिक्षा (Skill-based Education) इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप और प्रायोगिक अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है।

यदि शिक्षा प्रणाली में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकसित किए जाएँ, तो युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी और बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी। साथ ही, यह आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है।

10. प्रमुख चुनौतियाँ :

• क्षेत्रीय असमानता

भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों में काफी अंतर है, जिससे समान अवसरों का अभाव होता है।

• आधारभूत संरचना की कमी

कई विद्यालयों में पर्याप्त भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और तकनीकी संसाधनों का अभाव है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

• शिक्षकों की कमी

प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

• डिजिटल विभाजन

तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण सभी विद्यार्थियों को समान डिजिटल शिक्षा नहीं मिल पाती।

• गुणवत्ता की समस्या

रटने की प्रवृत्ति, पुराना पाठ्यक्रम और व्यावहारिक ज्ञान की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को सीमित करती है।

11. समावेशिता और समानता :

एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली वही होती है जो समाज के प्रत्येक वर्ग—जैसे गरीब, पिछड़े, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यक—को समान अवसर प्रदान करे। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 15 April 2026

इसके लिए नीतिगत प्रयासों के साथ साथ जागरूकता और संसाधनों का उचित वितरण आवश्यक है। जब सभी वर्गों को समान-शिक्षा प्राप्त होगी, तभी वास्तविक विकास संभव होगा।

12. शिक्षक शिक्षा :

शिक्षक शिक्षा किसी भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आधार होती है। एक प्रशिक्षित, प्रेरित और दक्ष शिक्षक ही विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान कर सकता है।

आधुनिक समय में शिक्षकों को नई तकनीकों, डिजिटल उपकरणों और नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। सतत प्रशिक्षण (Continuous Professional Development) के माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

13. मूल्य शिक्षा :

शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक और चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। मूल्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में ईमानदारी, सहिष्णुता, करुणा, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक और भौतिकवादी युग में मूल्य शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है।

14. भविष्य की संभावनाएँ :

भविष्य की शिक्षा प्रणाली तकनीकी नवाचारों पर आधारित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक बनाएँगी।

व्यक्तिगत अधिगम (Personalized Learning), ऑनलाइन शिक्षा, और वैश्विक सहयोग शिक्षा को अधिक लचीला और सुलभ बनाएंगे। साथ ही, बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा और अनुसंधान आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलेगा।

यदि इन संभावनाओं का सही उपयोग किया जाए, तो भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और प्रभावशाली बन सकती है।

15. निष्कर्ष:

आधुनिक भारत के समग्र विकास में शिक्षा की भूमिका केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि निर्णायक भी है। शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति निर्भर करती है। वर्तमान वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के युग में शिक्षा का स्वरूप भी व्यापक और बहुआयामी हो गया है। अतः एक-ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित न रहकर, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग—विशेषकर वंचित, पिछड़े, दिव्यांग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों—को समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। जब तक शिक्षा सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचेगी, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय और सतत विकास संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार कौशल आधारित शिक्षा-Skill-based Education) वर्तमान समय की मांग है, जो युवाओं को केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि रोजगारोन्मुख, आत्मनिर्भर और नवाचारशील बनाती है।

विकासोन्मुख शिक्षा (Development-oriented Education) राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में सहायक होती है, क्योंकि यह मानव संसाधन को उत्पादक और दक्ष बनाती है। साथ ही, मूल्यपरक शिक्षा (Value-based Education) व्यक्ति में नैतिकता, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवता जैसे गुणों का विकास करती है, जो एक सशक्त और सभ्य समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतियाँ जैसे—गुणवत्ता में असमानता, डिजिटल विभाजन, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, और संसाधनों की अपर्याप्तता—मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान प्रभावी नीतियों, नवाचार, तकनीकी समावेशन तथा सतत प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है। National Education Policy 2020 जैसे महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अंततः, एक समावेशी, कौशलआधारित-, विकासोन्मुख और मूल्यपरक शिक्षा प्रणाली ही भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनाने में सक्षम होगी। शिक्षा के माध्यम से ही "सशक्त भारत" का सपना साकार हो सकता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक न केवल शिक्षित बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और सृजनशील हो

संदर्भ (References):

1. Aggarwal, J. C. (2014). *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास* (Development of education system in India). शिप्रा पब्लिकेशन्स।
2. Agrawal, S. P. (2001). *भारत में शिक्षा: अतीत, वर्तमान और भविष्य* (Education in India: Past, present and future). कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
3. Ahmad, J., & Masih, A. (संपा.). (2023). *भारत में शिक्षण एवं शिक्षक शिक्षा: दृष्टिकोण, चिंताएँ एवं प्रवृत्तियाँ* (Teaching and teacher education in India: Perspectives, concerns and trends). स्प्रिंगर।
4. Altbach, P. G. (2016). *उच्च शिक्षा पर वैश्विक दृष्टिकोण* (Global perspectives on higher education). जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* (National education policy 2020). शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. Kumar, A. (2023). आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ और मुद्दे: एक समीक्षा। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज*, 5(2)।
7. Kumar, K. (2019). *भारत में शिक्षा की राजनीति* (Politics of education in India). रूटलेज इंडिया।
8. Naik, J. P. (1974). *भारतीय शिक्षा: स्वतंत्रता के बाद इसका विकास* (Indian education: Its development since independence). एलाइड पब्लिशर्स।
9. NCERT. (2021). *भारत में शैक्षिक सुधार* (Educational reforms in India). नई दिल्ली।
10. Padmavathi, K., आदि. (2024). भारत की शिक्षा प्रणाली के समकालीन मुद्दे, संभावनाएँ और चुनौतियाँ: एक संक्षिप्त अवलोकन। *यूरोपियन इकोनॉमिक लेटर्स*, 14(2)।
11. Saxena, S., & Agarwal, R. (2021). भारत की नई शिक्षा नीति 2020: प्रभाव, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ। *जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड*, 16(2)।
12. Tilak, J. B. G. (2015). *भारत में शिक्षा, विकास और समानता* (Education, development and equity in India). ओरिएंट ब्लैकस्वान।
13. Tilak, J. B. G. (2018). *भारत में उच्च शिक्षा: समानता, गुणवत्ता और मात्रा की खोज* (Higher education in India: In search of equality, quality and quantity). ओरिएंट ब्लैकस्वान।
14. Tilak, J. B. G. (संपा.). (2020). *भारत में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा: मुद्दे, चुनौतियाँ और संभावनाएँ* (Universal secondary education in India: Issues, challenges and prospects). स्प्रिंगर।
15. UNESCO. (2020). *कोविड-19 के बाद की दुनिया में शिक्षा* (Education in a post-COVID world). पेरिस।

16. Upadhyay, R., आदि. (2023). भारतीय शिक्षा प्रणाली: मुद्दे और चुनौतियाँ—एक समीक्षा। *जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस*, 5(1)।

Cite this Article:

डॉ. संतोष कुमार भारती, "आधुनिक भारत एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था : स्वरूप, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp-236–242, Volume-05, Issue-01, April-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. संतोष कुमार भारती

For publication of Research Paper title

आधुनिक भारत एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था : स्वरूप, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.27